उज्ज्वल भारत

2 वर्ष की

उपलब्धियाँ एवं पहल

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत सरकार

मई 2016

असीमित महत्वाकांक्षाओं के साथ नई उंचाइयों को हाँसिल करते हुए

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के उज्ज्वल भारत के सपने को साकार करने के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियाँ

1. DISCOMs की कायापलट के लिए विद्युत क्षेत्र में अब तक की सबसे व्यापक सुधार योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

2. रु.1 लाख करोड़ के उदय बॉण्ड्स जारी किए गए

3. बिजली से वंचित 7,108 गांवों में 2015-16 के दौरान बिजली पहुँचाई गई, जो पहले के 3 सालों के मुकाबले 37% ज्यादा है

4. मौजूदा पांरपरिक ऊर्जा क्षमता में 2014-2016 के दो सालों में पांचवें हिस्से (46,543 मेगावाट) जितनी वृद्धि की गई

5. 2012-14 के 46 सीकेएम की तुलना में 2014-16 के दो सालों में 69 सीकेएम प्रतिदिन ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गई

6. बिजली के घाटे का दर जो 2008-09 में 11.1% था, वो कम हो कर 2015-16 में 2.1% हुआ

7. 74 कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी और आवंटन से सभी कोयलाधारी राज्यों को खदानों के जीवनकाल के दौरान ₹ 3.44 लाख करोड़ रुपये का संभावित लाभ

8. कोयले के उत्पादन में साल 2014-16 के दो वर्षों में कोल इंडिया द्वारा 7.4 करोड़ टन का आज तक का सर्वाधिक विकास

9. 2014 से सौर ऊर्जा क्षमता में 4,132 मेगावाट की 157% बढ़ोती

10. 2015-16 में पवन ऊर्जा क्षमता में आज तक के सर्वाधिक 3,423 मेगावाट का इजाफा

11. 2015-16 में उजाला के तहत 9 करोड़ एल.ई.डी. बल्बों का वितरण, जो 2013-14 के 6 लाख की तुलना में 150 गुना ज्यादा है

12. 2015-16 में सर्वाधिक 31,472 सौर पंप लगाए गये, जो 1991 में यह कार्यक्रम लागू किये जाने के बाद की कुल संख्या से भी ज्यादा हैं

13. अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए मोबाइल एप्लीकेशन

- ग्रामीण विद्युतीकरण को ट्रैक करने के लिए GARV (गर्व) एप्लीकेशन
- वास्तविक समय में बिजली की कीमत और उपलब्धता पे निगरानी रखने के लिए विद्युत प्रवाह एप्लीकेशन
- एल.ई.डी. वितरण पे निगरानी रखने के लिए उजाला एप्लीकेशन

लक्ष्य

2019 तक सबके लिए सस्ती एवं पर्यावरण हितैषी 24 X 7 बिजली

जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने

सबके लिए 24 X 7 बिजली

सस्ती बिजली

पर्यावरण हितैषी

जो जुड़े नहीं हैं उनको जोड़ने

1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार **18,452** बिजली से वंचित गांवों में बिजली पहुँचाने की चुनौती

"125 करोड़ भारतवासियों की 'टीम इंडिया' की अब ये पवित्र प्रतिज्ञा है कि इन 18,500 गांवों में बिजली के खंभे , तार और बिजली पहुँचाने का लक्ष्य अगले 1,000 दिनों में हाँसिल कर लिया जाएगा"

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
15 अगस्त, 2015

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के अंतर्गत

2,800 के शुरुआती लक्ष्य की तुलना में 2015-16 में **7,108** गांवों में बिजली पहुँचाई गई

40%

गाँव अब तक जुड़ चुके हैं

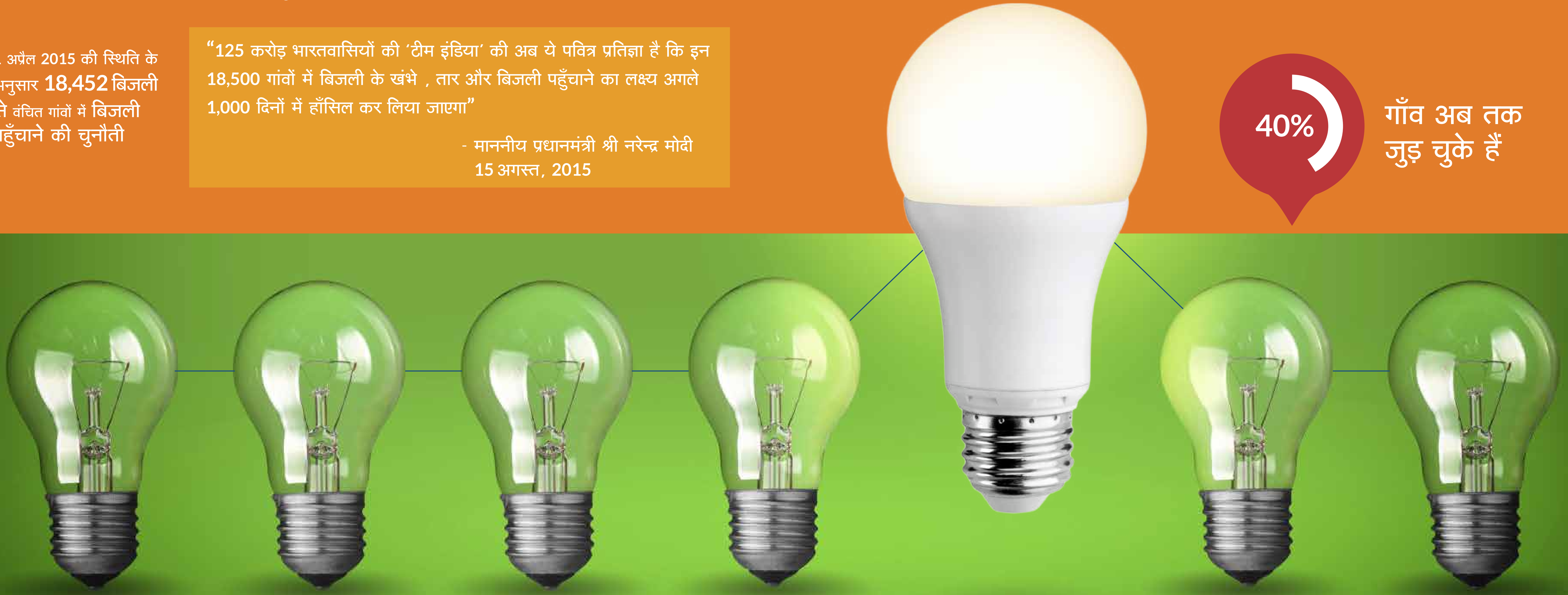

गर्व (GARV)

ग्रामीण विद्युतीकरण पर नज़र पारदर्शिता के लिए निरंतर प्रयास

ग्रामीण विद्युतीकरण पर निगरानी रखने हेतु नागरिकों के लिए गर्व (GARV) मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है

www.garv.gov.in

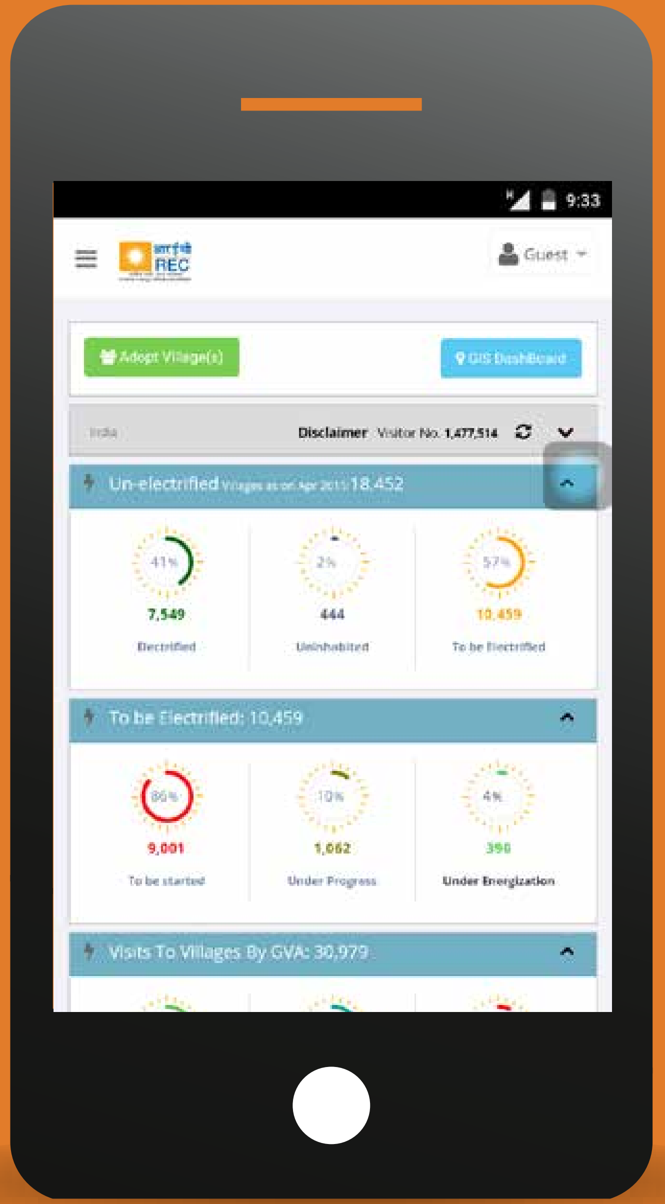

अँधेरे से उजाले की ओर

नुआंव गाँव, बिहार

निवासी अखिलेश कुमार सिंह जब गाँव में बिजली नहीं थी उस वक्त की समस्याओं को याद करते हुए। "गर्मी के मौसम में, घर में महिलाएं और बच्चे दिनभर लू का सामना करते थे। इसके अलावा, रात के समय कम रोशनी वाली जगहों पर सुरक्षा का खतरा मेहसूस होता था। बच्चे रात में अपनी पढ़ाई भी 'ढ़िबरी' या केरोसिन के दिए तले करते थे। हालाँकि, गाँव को बिजली मिल जाने से अब यह सब बदल गया है। अब सब गाँव वाले गर्मी से बचने के लिए पंखे चलाते हैं, रात में सुरक्षा बढ़ गई है और बच्चे अब एल.ई.डी. लाइट में पढ़ते हैं। अब आटा चक्की और मोटरों का भी गाँव में उपयोग हो रहा है।''

बदौरा गाँव, उत्तर प्रदेश

एक खुशहाल निवासी याद करता है, "मैं अपने जन्म से ही यहाँ रहता हूँ। डेढ़ महीने से बिजली आयी है। पहले कुछ नहीं हुआ था। कई अफसर लोग आये और वादे कर गये लेकिन फिर दिखाई नहीं दिए। हम पहले रोशनी के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग करते थे। अब हम हैण्ड पंप, हाथ आटा चक्की से मुक्त हो जाएँगे। बिजली खेतों में भी पहुँचेगी। बच्चे अब रात को भी पढाई कर पाएँगे। हमारे लिए यह बड़ा सुविधाजनक सुविधा है।"

सबके लिए 24 X 7 बिजली

कोयला: कोयले की खदान से बिजली घर तक

2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए गये **204 कोयला ब्लॉकों** में से **31 कोयला ब्लॉकों** की पारदर्शी नीलामी और **43** कोयला ब्लॉकों का आवंटन

कोयलाधारी राज्यों को खदानों के जीवनकाल के दौरान **3.44 लाख करोड़ रुपयों** का संभावित राजस्व

2014 में दो तिहाई मुख्य पावर प्लांटस के पास **7 दिन से भी कम** चले इतना कोयले का भंडार था |
आज एक भी पावर प्लांट में जोखिमपूर्ण कोयले के भण्डार की समस्या नहीं है |
औसत भण्डार **25 दिन की जरुरत से ज्यादा का है**

छोटे और मध्यम स्तर के ग्राहकों को बढ़ावा देने हेतु, कोयले की कीमतें, उपलब्धता और उपयोग की जानकारी देता हुआ कोयला आवंटन नियंत्रण प्रबंध [Coal Allocation Monitoring System (CAMS)] पोर्टल

कोल इंडिया

विशाल संगठन पुन:सक्रिय हुआ

अन्वेषण

अन्वेषण हेतु ड्रिलिंग में **44% वृद्धि**, 2012-14 के 12.6 लाख मीटर की तुलना में 2014-16 में 18.2 लाख मीटर

खान विकास

प्रति दो एकड़ भूमि अधिग्रहण पर एक नौकरी का आकर्षक प्रस्ताव देकर, भूमि अधिग्रहण को दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद बनाया गया

खनन

2020 तक कोल इंडिया का उत्पादन दुगना यानि कि 100 करोड़ टन करना

2015-16 में 53.60 करोड़ टन उत्पादन किया

2 साल की अवधि में अब तक की सर्वाधिक 7.4 करोड़ टन की वृद्धि

उत्पादन में 2010-14 के सिर्फ 1.8% की तुलना में 2014-16 में औसतन 7.7% की सालाना वृद्धि

गुणवत्ता

अब पावर प्लांट्स को 100% क्रश्ड (crushed) कोयला

2017-18 तक वॉशरी की सुविधा की क्षमता 3.7 करोड़ टन से चौगुनी होकर 15 करोड़ टन

कोयले के नमूने की तृतीय पक्ष से जाँच

निकासी

नए रेलवे रैक्स तथा लाइनों में निवेश करके, आधुनिकीकरण और यांत्रिकीकरण में तेज़ी लाकर कोयले की बेहतर निकासी को प्रोत्साहित करना

मूलभूत सुविधाओं के सृजन को मजबूती देने के लिए कोल इंडिया, रेलवे और कोयलाधारी राज्यों जैसे कि ओड़िशा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के बीच करार (MOUs)

परिणाम

2015-16 में कम आयात की वजह से लगभग 24,000 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की बचत

2016-17 में 40,000 करोड़ रुपयों तक की विदेशी मुद्रा की बचत करने का लक्ष्य

जलविद्युत ऊर्जा
की रीचार्जिंग

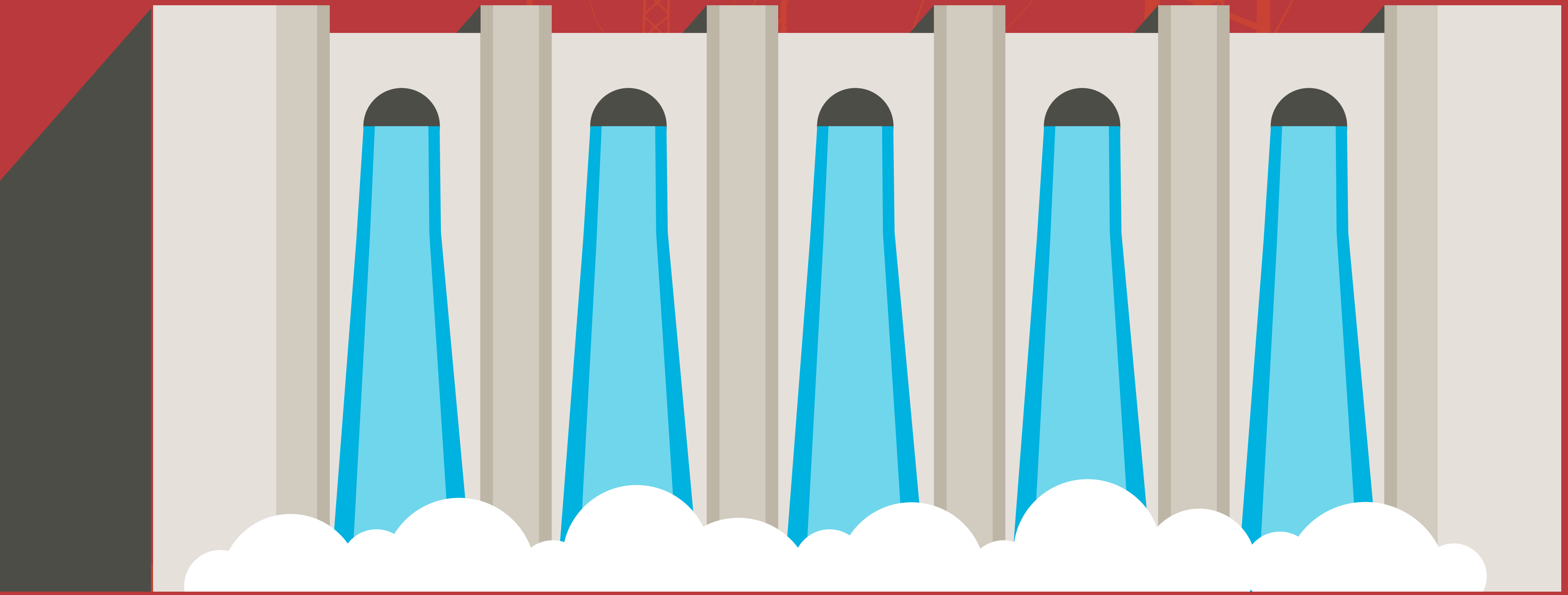

पुनः जल प्रवाह : पूर्वोत्तर राज्यों को स्वच्छ बिजली मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए
1,200 मेगावाट की तीस्ता जल विद्युत परियोजना को आर्थिक पुनर्गठन द्वारा पुनर्जीवित किया गया

विद्युत मंत्रालय के आधीन वित्तीय संस्थाओं ने पावर प्रोजेक्ट्स को लंबी अवधि के लिये ऋण देने का निर्णय लिया है जिससे खास तौर पर जलविद्युत परियोजनाओं को मदद मिलेगी

जलविद्युत को प्रोत्साहित करने के लिए टेरिफ नीति

2022 तक स्पर्धात्मक बोली से छूट देते हुए जलविद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में पूंजीगत लागत, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, भौमिकी और निर्माण अवधि जैसी समस्याओं का समाधान करना

वितरण लाईसेंसियों को 35 वर्ष के दीर्घकालीन पी.पी.ए. में 15 वर्ष की अवधि और बढ़ाने की अनुमति

राज्यों को जलविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे की निम्न दर टेरिफ का लाभ राज्य और उपभोक्ताओं को मिल सके

विद्युत उत्पादकों को 'टाइम ऑफ़ द डे' टेरिफ की अनुमति

जलविद्युत के द्वारा पीकिंग पावर के विस्तार को प्रोत्साहित करना

जलविद्युत को नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर.पी.ओ.) से अलग कर दिया गया है

जलविद्युत को उपभोक्ताओं के लिये ज्यादा आकर्षक बनाना

डेप्रिसियेशन दर में विकासकर्ताओं को रियायत दी गयी

ताकि शुरुआती वर्षों में कम टेरिफ रखे जायें

गेस प्लांट्स

पुन:र्जीवित किये गए

भारत की 24,150 मेगावाट ग्रिड-कनेक्टेड क्षमता में से 14,305 मेगावाट क्षमता वाले 29 गेस आधारित पावर प्लांट्स को 2014 में घरेलू गेस उपलब्ध नहीं थी

2015 में पारदर्शी ई-ऑक्शन के जरिए 11,717 मेगावाट क्षमता के असहाय प्लांट्स री-गेसीफाइड लिक्विफाइड गैस (RLNG) की पूर्ति द्वारा पुनर्जीवित किये गये

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी को गेस आधारित प्लांट्स से बढ़े हुए उत्पादन का लाभ मिला

- भीषण गर्मी के महीनों में, जब दक्षिण भारत में ट्रांसमिशन बाधाओं की वजह से बिजली की कमी रहती है, तब इससे विशेष राहत मिलेगी

ट्रांसमिशन

एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक मूल्य

2014-2016 के दो वर्षों में सर्वाधिक **50, 215 सी.के.एम.** ट्रांसमिशन लाइन्स डाली गयी, जो 2012-14 के दो वर्षों की 33,855 सी.के.एम. की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है

2014-16 के दो वर्षों के समय में सब-स्टेशन क्षमता में सर्वाधिक **1,28,403 एम.वी.ए.** की बढ़ोत्तरी

दक्षिण भारत (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी) की ट्रांसमिशन क्षमता जो 2013-14 में 3,450 मेगावोट थी, उसे **71% बढाकर** 5,900 मेगावोट की गयी। अगले

पावर ग्रिड ने 2015-16 में करीबन **₹30,300 करोड़** मूल्य की परियोजनाएँ चालू की जिससे **39%** वृद्धि हुई

2015-16 में लगभग **₹1 लाख करोड़** मूल्य की परियोजनाएँ शुरू की गईं

उदय
सशक्तिकरण सुधार

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना विद्युत क्षेत्र में आज तक का सब से ज्यादा व्यापक सुधार है

विद्युत मूल्य श्रृंखला में डिस्कॉम सबसे कमजोर कड़ी है

सालाना घाटा करीब 60,000 करोड़ रूपये का और 4.3 लाख करोड़ रूपये का संचित ऋण

डिस्कॉम की पिछली, वर्तमान और भावी समस्याओं का स्थायी समाधान

आर्थिक एवं परिचालन दक्षता में सुधार लाकर डिस्कॉम्स का टर्न-अराऊंड

भूतकाल
राज्य द्वारा ऋण का अधिग्रहण
ज्यादा हानियाँ

वर्तमान
वित्तीय दक्षता
परिचालन दक्षता
विद्युत का कम दाम

भविष्य
बजटीय अनुशासन
स्मार्ट अवसंरचना

सशक्त और जीवंत डिस्कॉम

भारत उदय

2015-16 में 1 लाख करोड़ रुपयों के उदय बॉण्ड्स जारी किये गये

18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में से

10 राज्यों ने समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं

8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने शामिल होने की सहमति दे दी है

टेरिफ नीति
सबके लिए बिजली

माइक्रोग्रिड्स द्वारा दूरस्थ गांवों को बिजली

वॉशरी रिजेक्ट्स कोयले के प्रयोग द्वारा कोयले की खदानों के पास सस्ती बिजली

तय पथ (defined trajectory) से सबको 24 X 7 बिजली आपूर्ति

अन्त्योदय
पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की सेवा

ग्रामोदय से भारत उदय के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)

अविद्युतीकृत शेष बचे 18,452 गांवों का विद्युतीकरण (1 अप्रैल 2015 के अनुसार)

ग्रामीण आवासों और सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योगों को 24 X 7 बिजली दने के लिए फीडर्स का पृथक्करण

किसानों को पर्याप्त मात्र में बिजली

नए ट्रांसफार्मर्स और लास्ट माइल अवसंरचना का सुधार

दूरवर्ती गांवों का समावेशः ऑफग्रिड्स और माइक्रोग्रिड्स

स्वच्छ और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए डिस्कॉम्स द्वारा सौर संस्थापना (इंस्टॉलेशन)

75,893 करोड़ रुपयों का परिव्यय

73,960 करोड़ रुपयों की स्वीकृत परियोजनाएं

शहरों में स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (IPDS)

घरों में स्मार्ट मीटरिंग और टेम्परप्रूफ मीटर

शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना का सुधार जिसमें व्यापक सब-ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है

घनी आबादी वाले इलाकों में भूमिगत (अंडरग्राउंड) केबलिंग और जी.आई.एस. सब-स्टेशन

बेहतर ग्राहक सेवा के लिए आई.टी. का प्रयोग

सौर संस्थापना जैसे कि छतों पर सौर पेनल्स भी शामिल

65,424 करोड़ रुपयों का परिव्यय

56,295 करोड़ रुपयों की स्वीकृत परियोजनाएं

सहकारी संघवाद

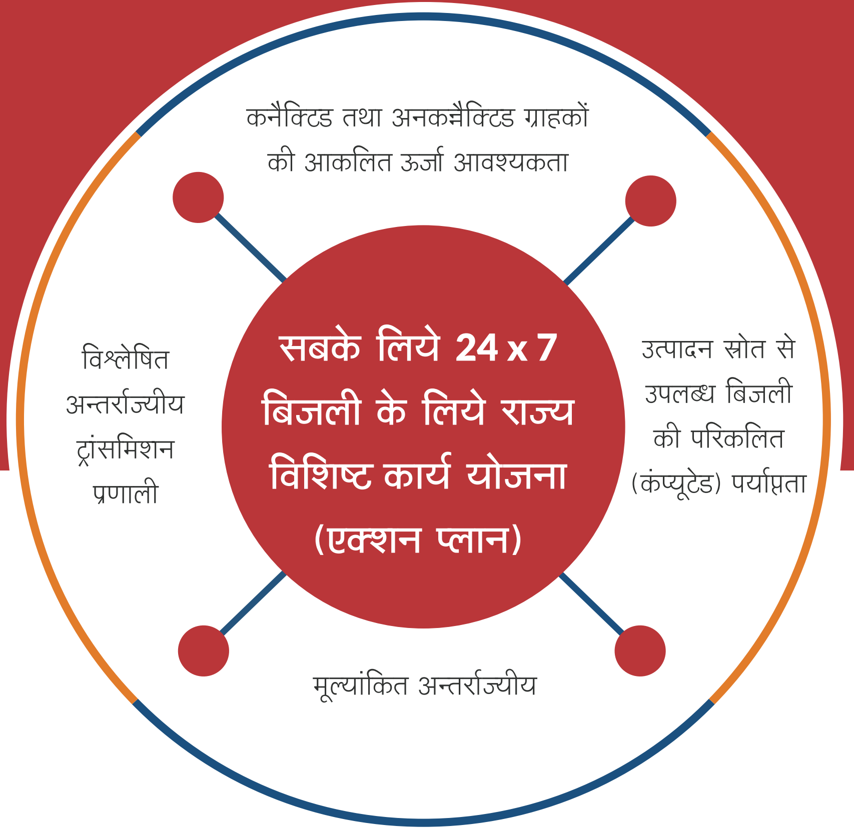

21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं

और 12 ने योजना को अंतिम रूप दे दिया है

3 योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं

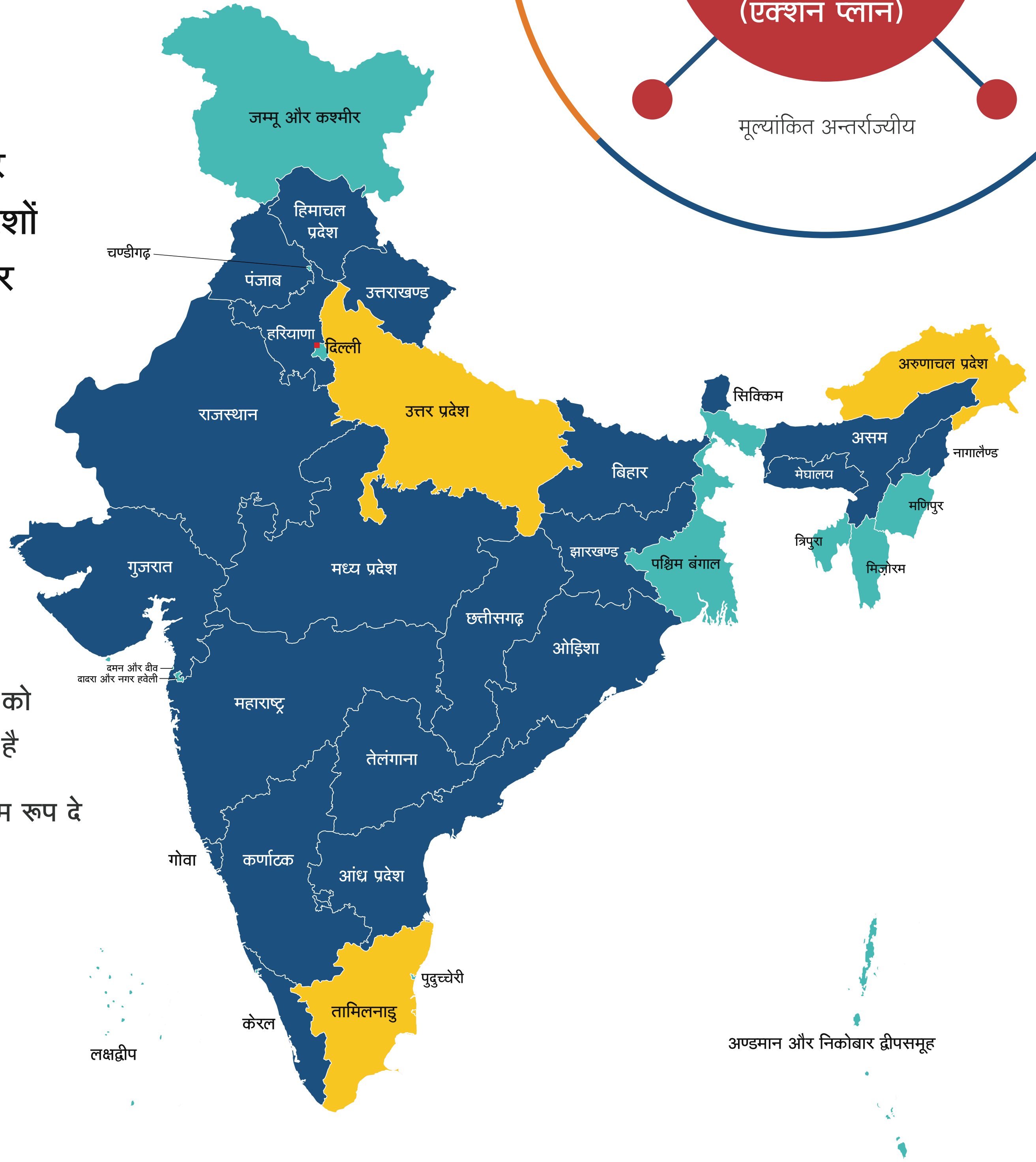

विद्युत प्रवाह नागरिकों का सशक्तिकरण

www.vidyutpravah.in

एप्लीकेशन बिजली के मूल्य और समय उपलब्धता की वास्तविक जानकारी देता है

सूचना देकर नागरिकों का सशक्तिकरण

राज्य सरकारों को जवाबदेह बनाया गया

Piyush Goyal @PiyushGoyal Follow

At this moment, 3,948 MW of surplus power available at Rs. 2.87/unit. Check status in your State at vidyutpravah.in

सस्ती बिजली

टेरिफ नीति

किफायती टेरिफ सुनिश्चित करने की दक्षता

मौजूदा पावर प्लांट्स के विस्तार के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत घटाना

न माँगी गयी बिजली की बिक्री से हुए लाभ को साझा करके कुल विद्युत लागत में कमी

प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये ट्रांसमिशन परियोजनाओं को विकसित करना जिससे कम कीमत पर जल्दी पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके

"टाइम ऑफ़ डे" मीटरिंग हो सके, चोरी कम की जा सके, और 'नेट-मीटरिंग' हो सके इसलिए स्मार्ट मीटर्स की त्वरित संस्थापना

पूरे भारत में विद्युत की पहुँच के लिए ट्रांसमिशन क्षमता सृजित करते हुए निम्न विद्युत लागत

राज्यों द्वारा अल्पकालीन बिजली की जरुरत के लिए नीलामी द्वारा खरीद अनिवार्य

उदय

डिस्कॉम्स की समस्याएँ समाप्त

डिस्कॉम्स की हानियों को घटाकर कम लागत वाली विद्युत की संभाविता

ऋण पर देय औसतन ब्याज खर्च को 12% से घटाकर 8% तक कम करने के लिए डिस्कॉम्स के ऋण का अधिग्रहण

समग्र वाणिज्यिक और तकनीकी (ए.टी. एण्ड सी.) हानियों को कम करने के लिए प्रचालन दक्षता

- मीटरिंग और ट्रैकिंग के माध्यम से बिलिंग दक्षता में सुधार
- अवसंरचना संवर्धन और स्मार्ट मीटरिंग
- जन भागीदारी से वसूली दक्षता में सुधार

प्रति यूनिट निर्धारित लागत कम करने के लिए प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाना

सामान्य परिस्थितियों में कारोबार में 2018-19 तक कार्यक्षमता/दक्षता सुधार लाभों के जरिये संभावित बचत

25% DISCOM ऋण पर 3%
75% DISCOM ऋण पर 4%
₹ 17,000 करोड़ रुपये
ब्याज दर में कमी

75% DISCOM ऋण पर 8%
₹ 27,000 करोड़
राज्य द्वारा ऋण अधिग्रहण

कम कर के 15%
₹ 33,000 करोड़
ए.टी.एंड सी. हानियाँ

कोयले की घटी हुई कीमत
₹ 36,000 करोड़
घरेलू कोयले की आपूर्ति और कोयले की स्वैपिंग

ऊर्जा दक्ष बल्ब, पंखे, ए.सी., कृषि पम्प्स इत्यादि
₹ 58,500 करोड़ रुपये
कार्यक्षमता सुधार के लिए मांग पक्ष का प्रबंधन

औद्योगिक ऊर्जा दक्षता
₹ 7,600 करोड़
बनाओ, अपनाओ और चलाओ (PAT)

1% अन्तर्राज्यीय हानियाँ
₹ 1,600 करोड़
ट्रांसमिशन हानियाँ

कुल ₹ 180,700 करोड़

थर्मल बढ़ते कदम

बढ़ती आपूर्ति

कीमतें घटाने एवं चोरी रोकने के लिये घरेलू कोयले की बढ़ती आपूर्ति

कोयले का लचीला उपयोग

दक्ष उत्पादन स्टेशन में घरेलू कोयले का लचीला उपयोग जिससे बिजली उत्पादन लागत कम हो और डिस्कॉम की खरीद लागत कम हो

कोयले लिंकेज

2.3 टन के विवेकपूर्ण उपयोग से ढुलाई खर्च में ₹ 1,371 करोड़ की बचत

कोयले के दाम

सही टैरिफ निश्चित करने के लिए ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (GCV)) पर आधारित रैशनेलाईजेशन

सौर टैरिफ 2010 के प्रति यूनिट ₹ 16-18 से ₹ 4.34-4.67 तक कम हुए (तेलंगाना में आखिरी बोली के अनुसार)

एन.टी.पी.सी. और एस.ई.सी.आई द्वारा सौर ऊर्जा खरीद करने से काउंटर पार्टी रिस्क में कमी

पर्यावरण संबंधी अनुमति को आसान करने के लिये सोलर प्लांट्स को हरित श्रेणी से श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत किया गया

बैंक फाइनेंसिंग को आसान करने के लिये प्राथमिकता लैंडिंग मानदण्डों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शामिल किया गया

नवीकरणीय पहुँच में

भारत ने एल.ई.डी. (LED) के मामले में विश्व की अगुआई की

- प्रधानमंत्री उजाला योजना (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) से भारत वैश्विक LED बल्ब बाज़ार में सब से ऊँचा स्थान लेने जा रहा है
- दुनिया का सबसे बड़ा LED वितरण कार्यक्रम जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब वितरित किये जा चुके हैं
- 2019 तक ज्यादा बिजली खर्च करने वाले 77 करोड़ बल्ब बदले जायेंगे
- पीक लोड मांग करीब 20,000 मेगावाट तक कम की जाएगी
- उपभोक्ता बिल करीब ₹40,000 करोड़ तक कम किये जायेंगे
- स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम (SLNP) के तहत 3.5 करोड़ परंपरागत स्ट्रीट लाइट्स बदली जाएंगी

पारदर्शी खरीद से LED की कीमत 82% तक कम हुई

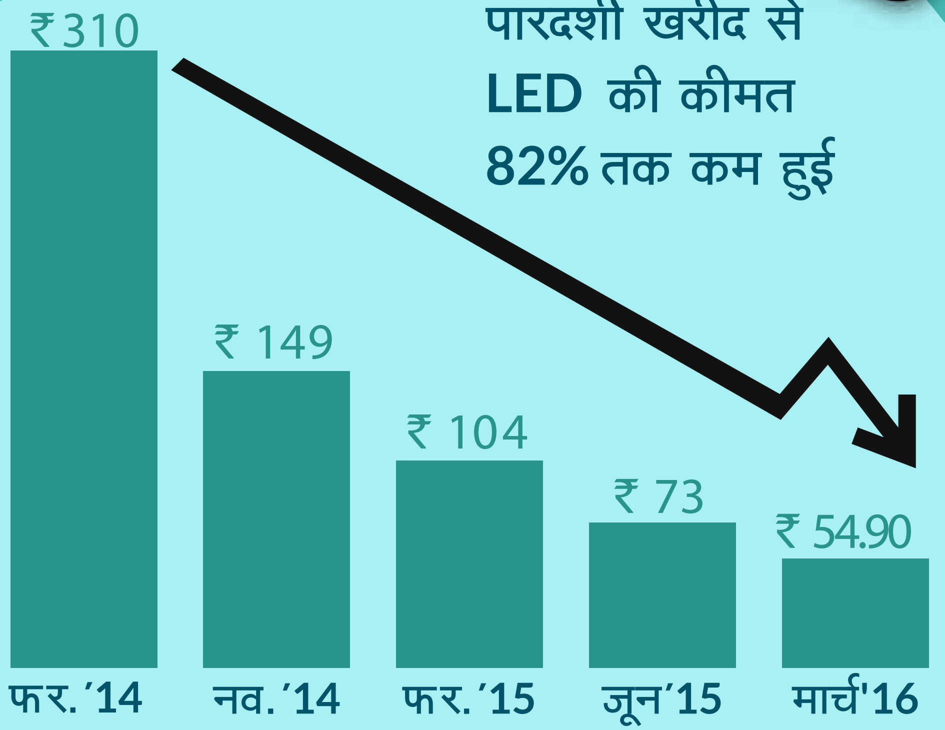

कम दामों में ज्यादा वाटेज,
7 वाट से 9 वाट

उजाला पर नजर रखना

विपिन आनंद

"पहले बल्ब जल्दी खराब होता था, 50 वाट खर्च करता था। बाद में सी.एफ.एल. का प्रयोग किया जो 12 वाट खर्च करता था। अब हम एल.ई.डी. उपयोग करते हैं जो सिर्फ 7 वाट खर्च करता है। मुझे आर्थिक लाभ हुआ है"

चारू मदान

"मैं पेशे से शिक्षक और गृहिणी हूँ। पहले जब मैं बिजली का बिल भरने जाती थी तो वह ज्यादा होता था। जबसे हमने LED बल्ब लगाए हैं, हमे फायदा हुआ है।"

उजाला पर नजर रखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन

www.ujala.gov.in

भारत का संकल्प

पर्यावरण हितैषी ऊर्जा

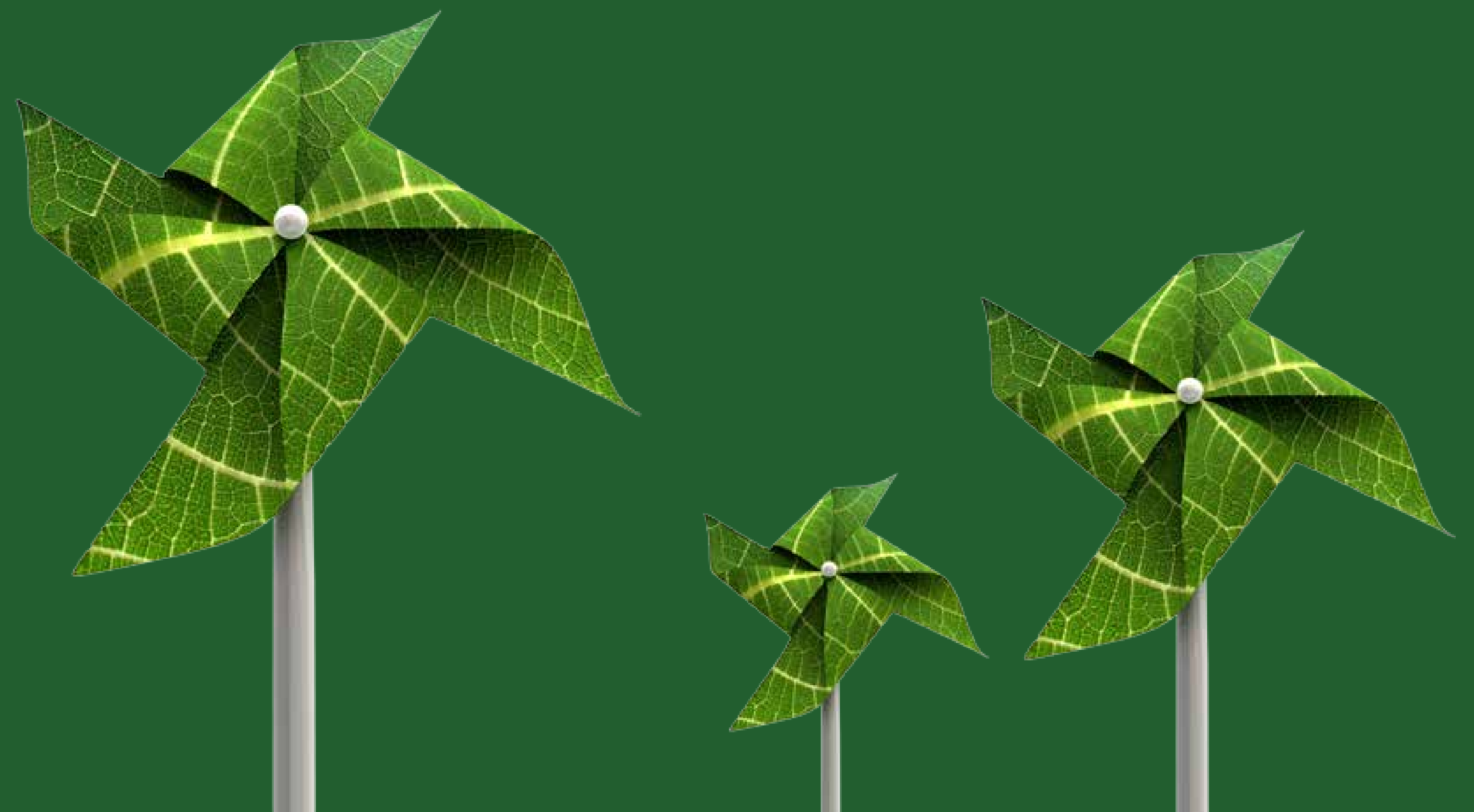

"नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत मेगावाट से गीगावाट की ओर बढ़ रहा है"

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

विश्व की स्वच्छ ऊर्जा राजधानी

2014 की 32 गीगावाट की नवीकरणीय क्षमता से 2022 तक समग्र रूप से 175 गीगावाट की बढ़ोतरी

- 100 GW सौर
- 60 GW पवन
- 10 GW जैव ईंधन ऊर्जा
- 5 GW लघु जल विद्युत

भारत विश्व में सब से बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम चला रहा है

पेरिस में हुए COP21 में 195 देशों के बीच जलवायु परिवर्तन का समझौता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

2030 तक अभिप्रेत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (INDC) में रिकॉर्ड लक्ष्य

- GDP उत्सर्जन 2005 के स्तर से 33-35% कम करना
- गैर-ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से लगभग 40% संचयी संस्थापित विद्युत क्षमता हासिल करना
- 250-300 करोड़ टन अतिरिक्तकार्बन सिंक का सृजन किया

अंतर्राष्ट्रीय सौर समझौता

वसुधैव कुटुम्बकम्

सौर ऊर्जा के उपयोग की महती सम्भावना के साथ 121 ट्रॉपिकल देशों से समझौता

सदस्य देशों में सौर ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग और संवर्धन तथा सौर ऊर्जा अनुप्रयोग बढ़ाने का साँझा लक्ष्य

2030 तक निवेश के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर्स (करीब ₹67 लाख करोड़) जुटाना

RE-INVEST 2015

विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय फाइनेंसिंग सम्मेलन

- 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना
- नवीकरणीय ऊर्जा के फंडिंग के लिए नए और मौलिक फाइनेंसिंग मॉडल्स विकसित करना

MAKE IN INDIA

2015 में

42 देशों से 2,860 प्रतिनिधि

29 देशों से 202 वक्ता

578 भारतीय और 124 अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ

7 देशों से 118 प्रदर्शक

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रीय कम्पनियों की हरित ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिबद्धता

अगला सम्मेलन
2017 में

266 GW
की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्रतिबद्धता

41 GW
के नवीकरणीय निर्माण की प्रतिबद्धता

अलग-अलग परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय फाइनेंसिंग की प्रतिबद्धता

नीति

धारणीय भविष्य के लिए पर्यावरण

मार्च 2022 तक सौर नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (RPO) में 8% वृद्धि

नए थर्मल और लिग्नाइट प्लांट्स पर नवीकरणीय उत्पादन दायित्व

सौर और पवन ऊर्जा के लिए कोई अन्तर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रभार और हानियाँ नहीं लगाई जायेंगी

कचरे से ऊर्जा प्लांट्स से 100% ऊर्जा खरीद अनिवार्य

नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए ग्रिड ऑपरेशन की मदद के लिए सहायक सेवाएँ

नेशनल ऑफशोर विंड इनर्जी नीति

तट से 200 नॉटिकल माईल तक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र [Exclusive Economic Zone (EEZ)] का विकास

बहुत जल्द गुजरात के समुद्र तट पर प्रथम परियोजना

उत्सर्जन में कमी

स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और गंगा जीर्णोद्धार की वित्त सहायता के लिये प्रति टन कोयले पर स्वच्छ पर्यावरण उपकर में 8 गुना वृद्धि करके इसे 50 रूपये से 400 रूपये किया गया

रिन्यूएबल इनर्जी सर्टिफिकेट्स (आर.ई.सी.) की बिक्री 2014-15 के 30.6 लाख की तुलना में 2015-16 में 62% बढ़कर 49.6 लाख हुई

2019 तक लगभग 7.9 करोड़ टन CO_2, ग्रीन हाउस गेस उत्सर्जन कम करने में उजाला सहायक होगा

2015-16 में **31,472 सोलर पम्प** लगाकर किसानों को मदद दी गयी, जो कि 1991 में शुरू की गयी योजना में तबसे अब तक लगाये गये कुल पम्पों की संख्या से ज्यादा है

ऊर्जा दक्ष LED पंखे और पम्पों की शुरुआत की गई

भविष्य के लिए निवेश

2015-16 में 20,904 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के टेंडर किये गये

नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए 38,000 करोड़ रूपये का ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर

20 राज्यों में 20,000 मेगावाट क्षमता वाले 33 सोलर पार्क

अनन्तपुरम्, आन्ध्र प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना

कुशल भारत

दीर्घकालिक समन्वित कौशल विकास परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एन.एस.डी.सी.) और राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.)

कोल इंडिया

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेम वर्क (NSQF) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक, अर्ध-कुशल श्रमिक और सम संचालन और उससे जुड़े क्षेत्रों में लगे युवाओं का समायोजन

2.7 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा

एन.टी.पी.सी.

पूरे देश में 22 स्थानों पर 5,000 लोगों को पहले 2 वर्षों में प्रशिक्षित किया जाएगा

मॉडल के रूप में एक मल्टी-मिशन संस्था स्थापित की जाएगी

बिहार के पिछड़े क्षेत्रों से **15,000 लोगों को** सेवा क्षेत्रों में और **10,000** लोगों को विनिर्माण क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के साथ एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये

2019-20 तक सूर्य मित्र योजना के अंतर्गत 50,000 सौर अभियन्ताओं को प्रशिक्षण

जलयुक्त भारत

बेहतर जल प्रबंधन

विद्युत क्षेत्र

पेय जल को बचाने और गंगा जैसी नदियों को स्वच्छ करने के लिए, पावर प्लान्ट्स् उपचारित दूषित जल का उपयोग कर नमामि गंगे में योगदान करेंगे

Namami Gange

कोयला क्षेत्र

खदान जल की उद्योगों, घरेलू और खेती के लिए आपूर्ति की जायेगी

जल साधनों का अनुरक्षण

खनन के बाद खाली जगहों को जल संसाधनों के रूप में भूजल रीचार्ज करने के लिए रखा गया

सूखे का सामना

भूमिगत जल संग्रह से नजदीकी गाँवो को पानी देकर कोयले की खदानें (खानें) सूखा पीड़ित क्षेत्रों की सहायता करती हैं

पश्चिमी कोयला क्षेत्र सावनेर भूमिगत खान से पानी छोड़कर नागपुर जिले के सूखा ग्रस्त बोरगाँव को पानी देता है जिससे जलस्तर में वृद्धि हुई है

अक्टूबर 2015 से पश्चिमी कोयला क्षेत्र, काँपटी खुली खान से, जल के अभाव से पीड़ित कान्हा नगर को जल आपूर्ति कर रहा है

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत

तीन मंत्रालयों के आधीन PSUs ने सक्रिय रूप में 1,28,000 शौचालय स्कूली लड़के और लड़कियों के लिए बनाये, खास तौर पर बिहार, ओड़ीशा, वेस्ट बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में

PSUs 5 साल के लिए उपयोग और देख-रेख सुनिश्चित करने के लिए शौचालयों का अनुरक्षण करेंगे

ग्रामीण समाज में स्वच्छता सुधार के लिए भी जागरूकता लाई जा रही है

ईको टूरिज्म अतुल्य भारत

नागपुर के नज़दीक वेस्टर्न कोल फ़ील्ड्स ने एक विशिष्ट ईको पार्क बनाया है

खान संबंधी गतिविधियाँ दिखाने के लिये गोंदेगाँव खुली खान तथा सावनेर भूमिगत खान का दौरा

मुख्य आकर्षण

- खनन प्रक्रिया का गाइडेड टूर
- टॉय ट्रेन में फॉरेस्ट सफारी

खेलकूद

कोल इंडिया ने खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के द्वारा अच्छी भूमिका निभाई

खेलकूद अकादमी और खेलकूद यूनिवर्सिटी होत्वर, रांची में मौजूद विश्वस्तरीय स्टेडियम स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

भविष्य की योजना

- सुंदरगढ़, ओड़ीशा में हॉकी एक्सीलेंस सेंटर
- सिंगरौली, मध्य प्रदेश में एथलेटिक्स अकादमी स्थापित करना

सत्यमेव जयते

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत सरकार

"आज़ादी के इतने साल हो गए। आज़ादी के इतने सालों के बाद इस देश के 18,000 गाँव ऐसे हैं, जहाँ बिजली का खम्भा भी नहीं पहुंचा है, बिजली का तार नहीं पहुँचा है। 18वीं शताब्दी में जैसी ज़िन्दगी वो गुजारते थे; 21वीं सदी में भी 18,000 गाँव ऐसे ही ज़िन्दगी जीने के लिए मजबूर हैं। मुझे बताओ मेरे प्यारे भाइयों-बहनों, क्या किया इन गरीबी के नाम पर राजनीति करने वालों ने? उन 18,000 गाँव को बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? मैंने बीड़ा उठाया है, लाल किले से 15 अगस्त को मैंने घोषणा की, मैं 1,000 दिन में 18,000 गाँवों को बिजली पहुंचा दूंगा। रोज का हिसाब देता हूँ देशवासियों को।"

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी

www.ujwalbharat.gov.in

@UjwalBharat